जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 33 संख्याः 83 प्रभात उदयपुर, शनिवार 24 जनवरी, 2026 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

दिल्ली में हुई केरल प्रदेश कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर

चर्चा है कि वे राहुल गांधी से उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण ख़फा हैं

- सूत्रों ने कहा कि थरूर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, कोझीकोड़े लिटरेचर फैस्टिवल में व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, हालांकि, पूर्व में यह भी खबर थी कि वे केरल के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे।
- काफी समय से थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के रिश्ते खराब चल रहे हैं, खासकर थरूर द्वारा समय-समय पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के कारण।
- थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के रूख की तारीफ की और यही नहीं, भारत सरकार ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष रखने के लिए विदेश दौरे पर जाने वाली टीम में भी शामिल किया था।
- कांग्रेस में बार-बार यह आरोप लग रहा है कि थरूर भाजपा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि जिसका थरूर ने खंडन भी किया है।
- लेकिन थरूर के कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल नहीं होने से यह तल्खी बढ़ती जा रही है और अटकलों का बाज़ार भी गर्म हो रहा है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। ऐसी खबरें हैं कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जिनके बारे में खबरें हैं कि वे राहुल गांधी से पर्याप्त सम्मान नहीं मिलने के कारण "नाराज" हैं। उम्मीद थी कि वे केरल विधानसभा चुनाव, जो इस साल के अंत में होने वाले हैं, की तैयारियों की समीक्षा के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। थरूर के करीबी सूत्रों ने पूर्व में कहा था कि वे बैठक में वर्चुअली भाग लेंगे।

सत्रों के मुताबिक, थरूर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण मीटिंग में नहीं आए। उन्हें कोझिकोडे लिटरेचर फैस्टिवल में भाग लेना था।

कांग्रेस के राज्य इकाई के प्रमुख नेताओं की गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में इस दोपहर मुलाकात हुई। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम से चार बार के सांसद, थरूर से उम्मीद की जा रही थी कि वे बैठक में शामिल होंगे, हालांकि इन दिनों पार्टी से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और वे पहले भी कांग्रेस पार्टी की कई मीटिंग्स में नहीं आए।

जाने माने कूटनीतिज्ञ थरूर के कांग्रेस नेतृत्व के साथ तलख रिश्ते हैं, खासकर उनके द्वारा प्रधानमंत्री और सत्ताधारी भाजपा की प्रशंसा करने वाले टिप्पणियों के कारण।

इनमें अप्रैल 22 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर (पाकिस्तान पर प्रतिशोधी सैन्य हमले) के संदर्भ में प्रधानमंत्री की सराहना करने वाले बयान शामिल हैं, साथ ही पार्टी और उसके नेतृत्व के मुद्दों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज हाई कोर्ट में कार्यदिवस, वकील पैरवी नहीं करेंगे

- वकीलों की शिकायत है कि उन्हें पाँच जनों की कमेटी की रिपोर्ट की जानकारी दिये बिना शनिवार की सूची बनाई गई।

जयपुर, 23 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा इस साल से माह में दो शनिवार न्यायिक कार्य दिवस घोषित करने पर शनिवार को वर्किंग डे रहेगा, हालांकि वकीलों ने विरोध स्वरूप स्वेच्छा से न्यायिक कार्य से दूर रहकर पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया है। वकीलों में इस बात का भी रोष है कि मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट से वकीलों को अवगत नहीं कराया गया। ऐसे में हाईकोर्ट बार, जयपुर और जोधपुर स्थित एडवोकेट्स एसोसिएशन व लॉयर्स एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है।

हाईकोर्ट बार अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने बताया कि पूर्व में इस संबंध में विवाद होने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने पांच जजों की कमेटी बनाई थी। जिसे 21 जनवरी तक एक्टिंग सीजे को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट की जानकारी एसोसिएशन को नहीं दी गई और शनिवार को मुकदमों की सुनवाई की सूची जारी कर दी गई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अगले सप्ताह एमेज़ॉन 14,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगा

ये सभी पद मैनेजमैंट वर्ग से संबंधित हैं

- कंपनी से जुड़े दो लोगों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि यह सब एआई की वजह से हो रहा है।
- ज्ञातव्य है कि एमेज़ॉन ने 30,000 कर्मचारियों की छंटनी का लक्ष्य तय किया है। इसका पहला चरण गत वर्ष अक्टूबर में हुआ था, जिसमें 14,000 कर्मचारी निकाले गए थे और दूसरा चरण मंगलवार को हो सकता है, उसमें भी इतने ही कर्मचारी निकाले जाएंगे।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। एमेज़ॉन 30 हजार कर्मचारियों की छंटनी करने के व्यापक लक्ष्य के तहत, अगले सप्ताह कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रहा है। यह जानकारी मामले से परिचित दो व्यक्तियों को दी।

कंपनी ने अक्टूबर में मैनेजमैंट से संबंधित लगभग 14,000 नौकरियाँ कम की थीं, जो कि 30,000 के लक्ष्य का लगभग आधा था, जैसा कि पहले रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था। इस बार कुल संख्या पिछले वर्ष के समान ही होने की संभावना है और यह मंगलवार से शुरु हो सकती है, जिन लोगों ने यह जानकारी दी, उन्होंने नाम गोपनीय रखते हुए कहा कि उन्हें एमेज़ॉन की योजनाओं पर चर्चा करने की अनुमति नहीं है।

लेकिन एमेज़ॉन के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार किया।

कंपनी के एमेज़ॉन वेब सर्विसेज, रिटेल, प्राइम वीडियो और मानव संसाधन (जिसे "पीपल एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है) विभागों में कर्मचारियों की छंटनी होने की संभावना है, हालांकि इसका पूर्ण विवरण स्पष्ट नहीं था। इन लोगों ने यह भी चेतावनी दी कि एमेज़ॉन की योजनाओं के विवरण में बदलाव हो सकता है।

सिएटल ऑनलाइन रिटेलर ने अक्टूबर में की गई छंटनी को आर्टिफिशियल इन्टैलिजैंस सॉफ़्टवेयर के बढ़ते प्रभाव से जोड़ा था, और एक आंतरिक पत्र में कहा था कि "एआई की यह पीढ़ी इंटरनेट के बाद सबसे परिवर्तनकारी तकनीक है, और यह कंपनियों को पहले से कहीं अधिक तेजी से नवाचार करने की क्षमता प्रदान कर रही है।"

हालांकि, कंपनी के सीईओ एंडी जैसी ने कंपनी की तीसरी तिमाही की आय पर विश्लेषण के दौरान विश्लेषकों से कहा था कि यह छंटनी "वास्तव में वित्तीय कारणों से नहीं है और न ही यह पूरी तरह से एआई से प्रेरित है। इसके बजाय, एक तरह का चलन है, यानी कंपनी में बहुत अधिक नौकरशाही हो गई है।"

उन्होंने कहा, जब कंपनी बढ़ती है तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाती है और उनके स्तर भी बढ़ जाते हैं।"

जैसी ने पहले 2025 में कहा था कि वे उम्मीद करते हैं कि एमेज़ॉन का कॉर्पोरेट कार्यबल धीरे-धीरे घटेगा, क्योंकि एआई के उपयोग से दक्षताएँ प्राप्त होंगी।

कंपनियाँ लगातार एआई का उपयोग अपने सॉफ़्टवेयर के लिए कोड लिखने और सामान्य कार्यों को स्वचालित करने वाले एआई एजेंटों को अपनाने में कर रही हैं, क्योंकि वे लागत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट जज से उलझने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई

वकील महेश तिवारी ने हाई कोर्ट द्वारा जारी अपराधिक अवमानना नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की

- ज्ञातव्य है कि वकील महेश तिवारी ने गत वर्ष 16 अक्टूबर का झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार के साथ तीखी बहस की और उन्हें हद पार नहीं करने की चेतावनी तक दे डाली थी। इस पर उन्हें अपराधिक अवमानना का नोटिस मिला था और बहस का वीडियो भी वायरल हो गया।
- महेश तिवारी को अवमानना नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आने पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी फटकार लगाई।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 23 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील को कड़ी फटकार लगाई, जिसने पिछले साल कोर्ट रूम में झारखंड हाई कोर्ट के एक जज के साथ हुई जुबानी झड़प को लेकर, उसको जारी किए गए क्रिमिनल कंटेम्प्ट (अपराधिक अवमानना) नोटिस के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की थी।

वकील महेश तिवारी ने 16 अक्टूबर को न्यायमूर्ति राजेश कुमार के साथ तीखी बहस की थी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बहस के दौरान, तिवारी ने न्यायमूर्ति कुमार से कहा था, आप "सीमा पार नहीं करें।"

झारखंड हाई कोर्ट ने इसके बाद तिवारी के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए थे।

लेकिन, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तिवारी को हाई कोर्ट की कन्टेम्प्ट प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आने के लिए फटकार लगाते हुए कहा, "वे सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक आदेश चाहते थे, ताकि वे दिखा सकें कि आपने "क्या बिगाड़ लिया मेरा।"

चीफ जस्टिस ने कहा, "अगर वे माफी मांगना चाहते हैं, तो माफी मांगें। अगर वे जजों को आंख दिखाना चाहते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, और फिर हम भी देखेंगे।"

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि तिवारी माफी मांगते हैं, तो हाई कोर्ट को भी इसे सहानुभूतिपूर्वक देख लेना चाहिए।

महेश तिवारी ने न्यायमूर्ति राजेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दुष्कर्म मामले में आरोपी क्रिकेटर को अनुसंधान में शामिल होने के निर्देश

- हाई कोर्ट ने क्रिकेटर को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई।

जयपुर, 23 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने से जुड़े मामले में आरोपी क्रिकेटर यश दयाल को तीस जनवरी तक जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में शामिल होने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने यश दयाल को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश यशदयाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया कि पीड़िता साल 2023 में कानपुर में घटना होना बता रही है, जबकि मामला दो साल बाद जयपुर के सांगानेर थाने में दर्ज कराया है। इसके अलावा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बांग्लादेश चुनावों में दखल दे रहा है अमेरिका'

बांग्लादेश की निर्वासित प्र.मंत्री शेख हसीना ने एक रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज में आरोप लगाया

- भारत में निर्वासित जीवन जी रही शेख हसीना ने बांग्लादेश की अराजकता और हिंसा के लिए पहली बार यूनुस सरकार की कड़ी आलोचना की।
- शेख हसीना ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अमेरिकन डिप्लोमैट्स इस्लामी चरमपंथियों से संपर्क कर रहे हैं।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना देश छोड़कर भागने के बाद, सार्वजनिक रूप से पहली बार वहां की मौजूदा सरकार की लगातार अराजकता और कानून व्यवस्था की खराब हालत के लिए आलोचना की है।

नई दिल्ली के फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स क्लब में चलाए गए एक रिकॉर्डेड ऑडियो संदेश में, शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस और अंतरिम प्रशासन को सीधे तौर पर अपने देश में बढ़ती अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मौजूदा शासन केवल विदेशी ताकतों की सेवा कर रहा है और आम लोगों की वास्तविक समस्याओं को नज़रअंदाज़ कर रहा है।

संकेतों में उन्होंने कहा कि अमेरिका देश की चुनाव प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप कर रहा है। साथ ही ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई हैं, जिनसे साफ संकेत मिलता है कि बांग्लादेश में अमेरिकी राजनयिक इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क बना रहे हैं और अशांत हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

रिपोर्ट साफ बता रही हैं कि अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि बांग्लादेश के उत्तरी जिले सिलहट गए थे, जहां उन्होंने जमात-ए-इस्लामी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह संगठन भारत-विरोधी और पाकिस्तान-समर्थक के रूप में जाना जाता है। ये लोग बांग्लादेश को एक कट्टर इस्लामी राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहे हैं।

बांग्लादेश में दो महीनों में संसदीय चुनाव होने हैं और सत्ता हासिल करने के लिए जोरदार जोड़-तोड़ चल रही है। पूरा चुनावी माहौल काफी हद तक भारत से रिश्तों के मुद्दे पर टिका हुआ है। हालांकि बांग्लादेश को पाकिस्तान की सेना से आज़ाद कराने में भारत की अहम भूमिका रही थी, लेकिन इसके बावजूद, देश जल्दी ही एक इस्लामी गणराज्य में बदल गया और भारत-विरोधी रुख अपनाने लगा

1971 में आज़ादी पाने के तुरंत बाद, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी शेख मुजीबुर रहमान की नृशंस हत्या कर दी गई। इसके बाद, एक के बाद एक, सैन्य तख्तापलट हुए और लोकतंत्र काफी समय बाद जाकर बहाल हो पाया।

लेकिन करीब डेढ़ साल पहले शेख हसीना की सरकार की बेदखली के बाद, देश पूरी तरह अराजकता और कानूनहीनता की स्थिति में डूब गया। बांग्लादेश में जमातियों का मुख्य गुस्सा खास तौर पर हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ देखने को मिला।

शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदुओं पर हमलों की अनेक घटनाएं हुई हैं और कई हिंदू युवकों की खुलेआम हत्या की गई है। एक मामले में एक हिंदू गारमेंट फैक्ट्री कर्मचारी को पीट-पीटकर मार डाला गया और बाद में उसके शव को ठोकरें मारी गईं और आग लगा दी गई।

इस घटना से पूरी दुनिया में भय और आक्रोश पैदा हुआ था, जिसमें अमेरिका के कुछ सांसद भी शामिल थे। लेकिन अब वही अमेरिकी प्रशासन वहां के इस्लामी तत्वों से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जमातियों से बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

भारत के पड़ोस में अमेरिका की यह गतिविधि भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'चीन के पास फ्री पास था, भारत के पास यह सुविधा नहीं होगी'

भारती ग्रुप के सीईओ सुनील भारती मित्तल के इस कथन में निहित है नई ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी की वास्तविकता

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। दावोस में भारती समूह के संस्थापक सुनील भारती मित्तल की यह सीधी टिप्पणी, "चीन को फ्री पास मिला था, भारत को नहीं मिलेगा", आज की नई वैश्विक व्यापार सच्चाई को साफ तौर पर दिखाती है।

विश्व आर्थिक मंच में बोलते हुए मित्तल ने कहा कि वे दो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सीधी तुलना नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि वैश्विक व्यापार के नियम अब गहराई से बदल चुके हैं, और भारत की सफलता चीन मॉडल की पुरानी यादों पर नहीं, बल्कि बड़े पैमाने, मजबूती और रणनीतिक आत्मविश्वास पर निर्भर करेगी।

चीन का निर्यात आधारित उदय ऐसे समय में हुआ, जब वैश्वीकरण बेहद उदार दौर से गुजर रहा था। करीब तीन दशकों तक पश्चिमी देशों ने अपने उद्योगों की सुरक्षा से ज्यादा सस्ती वस्तुओं और कम महंगाई को प्राथमिकता दी। व्यापार घाटे बढ़ ते रहे, सरकारी सब्सिडी को नजरअंदाज किया गया और भू-राजनीतिक जोखिमों को हल्के में लिया गया। चीन ने इस माहौल का पूरा फायदा उठाया, बड़े पैमाने पर मैनुफैक्चरिंग कपैसिटी (विनिर्माण क्षमता) खड़ी की, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से गहराई से जुड़ा और कड़ा विरोध शुरू होने से पहले ही विश्व अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन गया।

मित्तल ने कहा, भारत के पास यह सुविधा नहीं है। अब वैश्विक माहौल सख्त हो चुका है। व्यापार अब सिर्फ दक्षता का मामला नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा, राजनीति और भरोसे से भी जुड़ गया है। टैरिफ फिर लौट आए हैं, औद्योगिक नीति दोबारा चर्चा में है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को इस तरह बदला जा रहा है कि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को तेजी से संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे माहौल में किसी भी देश को बिना विरोध के चीन जैसी पकड़ बनाने नहीं दी जाएगी। भारत के हर कदम पर उसकी प्रगति को परखा जाएगा, उस पर बातचीत होगी और चुनौती दी जाएगी।

फिर भी मित्तल का मूल तर्क आशावादी था। "फ्री पास" नहीं मिलने का मतलब यह नहीं कि मौके खत्म हो गए हैं। बल्कि इसका अर्थ है कि भारत को अलग रणनीति अपनानी होगी। उनके अनुसार, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका पैमाना है, आर्थिक, जनसंख्यात्मक (डैमोग्राफिक) और रणनीतिक। लगभग 1.5 अरब लोगों का घरेलू उपभोक्ता आधार वैश्विक बातचीत में भारत की स्थिति को पूरी तरह बदल देता है। जो देश केवल विदेशी बाजारों पर निर्भर हैं, उनके मुकाबले भारत अपनी विशाल और बढ़ ती माँग तक एक्सैस (पहुँच) देता है। इससे भारत कमजोर स्थिति से नहीं, बल्कि मजबूती से बातचीत कर सकता है। मित्तल ने जोर दिया कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढ ांचे में तेजी से हो रहे सुधार से इस लाभ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)